



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 85]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 1, 2017/फाल्गुन 10, 1938

No. 85]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 1, 2017/PHALGUANA 10, 1938

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 15 फरवरी, 2017

सं. टीएएमपी/20/2010-केपीटी।—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, एतद्वारा केपीटी की गांधीधाम टाउनशिप भूमि की वर्तमान दर संरचना की वैधता का इसके साथ संलग्न आदेश के अनुसार, विस्तार करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला संख्या टीएएमपी/20/2010-केपीटी

कांडला पत्तन न्यास

- - -

आवेदक

गणपूर्ति

- (i) श्री टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)
- (ii) श्री रजत सच्चर, सदस्य (आर्थिक)

आदेश

(फरवरी, 2017 के 8वें दिन पारित)

यह मामला कांडला पत्तन न्यास (केपीटी) की गांधीधाम टाउनशिप भूमि की दर संरचना की वैधता के विस्तार के लिए केपीटी द्वारा दायर प्रस्ताव से संबंधित है।

2. कांडला पत्तन न्यास (केपीटी) की गांधीधाम टाउनशिप भूमि के पट्टा किराये इस प्राधिकरण द्वारा पिछली बार 9 अप्रैल, 2012 के आदेश द्वारा संशोधित किया गया था और संशोधित पट्टा किरायों को 1 जनवरी, 2009 से पूर्वव्यापी प्रभाव दिया गया था ताकि वैधता 5 वर्ष के लिए अर्थात् 31 दिसंबर, 2013 निर्धारित की गई थी। तत्पश्चात् इस प्राधिकरण द्वारा केपीटी के अनुरोध पर केपीटी की गांधीधाम टाउनशिप भूमि की दर संरचना की वैधता का समय-समय पर विस्तार किया जाता रहा है।

3. केपीटी की गांधीधाम टाउनशिप भूमि के मौजूदा दर संरचना की वैधता का पिछला विस्तार केपीटी के अनुरोध पर 06 मई, 2016 के आदेश संख्या टीएएमपी/20/2010-केपीटी के द्वारा 30 सितंबर, 2016 तक अथवा केपीटी द्वारा दायर किए जाने वाले प्रशुल्क प्रस्ताव के आधार पर संशोधित किरायों की अधिसूचना के प्रभाव की तारीख तक, जो भी पहले हो, किया गया था।

4. केपीटी ने 11 अप्रैल, 2016 के ई-मेल द्वारा गांधीधाम टाउनशिप भूमि की दर संरचना के संशोधन का अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। प्रस्ताव को हितधारकों के साथ परामर्शी प्रक्रिया में लिया गया था। मामले में 30 जुलाई, 2016 को संयुक्त सुनवाई का आयोजन हुआ। केपीटी ने हमारे 2 अगस्त, 2016 के द्वारा मांगी गई सूचना/स्पष्टीकरण अपने 2 दिसंबर, 2016 के पत्र के द्वारा प्रस्तुत की है।

5.1 संशोधित भूमि नीति दिशानिर्देश (एलपीजी) 2014 का पैरा 5.7 बताता है कि यह नीति केपीटी, मुंबई पत्तन न्यास (एमबीपीटी) और कोलकाता पत्तन न्यास (केओपीटी) टाउनशिपों से संबंधित भूमि को छोड़कर, जिनके लिए अलग से नीति बनायी जायेगी, सभी महापत्तनों के लिए लागू है। अतः हमारे 10 अप्रैल, 2014 और 9 फरवरी, 2016 के पत्र संख्या टीएएमपी/8/2014-सामान्य के द्वारा एमओएस को यह अनुरोध किया गया था कि यह स्पष्ट किया जाए कि जब तक अलग से नीति नहीं बनती तब तक कांडला के टाउनशिप क्षेत्र की दरों का संशोधन किस एलपीजी के अंतर्गत शामिल किया जाये। इसके उपरांत 22 अप्रैल, 2016, 28 जून, 2016 और 14 जुलाई, 2016 को भी पत्र भेजे गए थे।

5.2 इस संदर्भ में, एमओएस ने अपने 2 अगस्त, 2016 के पत्र संख्या 8/(19)/2016-टीएएमपी के द्वारा सूचित किया है कि गांधीधाम टाउनशिप से संबंधित भूमि पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुमोदन प्राप्त करने का प्रस्ताव एमओएस द्वारा बनाया जा रहा है। इसलिए, एमओएस ने केपीटी के गांधीधाम टाउनशिप की दर संरचना के संशोधन के केपीटी के प्रस्ताव को रोके रखने और इस संबंध में एमओएस द्वारा नीति की संसूचना के पश्चात् आरंभ करने का अनुरोध किया।

5.3 इस बीच केपीटी ने अपने 18 नवंबर, 2016 के अपने पत्र द्वारा इस प्राधिकरण को अनुरोध किया कि उसे 6 महीने की और अवधि, अर्थात्, 31 मार्च, 2017 तक के लिए वर्तमान दरें इस शर्त पर जारी रखने की अनुमति दी जाए, कि संशोधित दरें पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू की जायेंगी।

5.4 ऊपर पैरा 5.2 में बतायी स्थिति को देखते हुए, एमओएस से गांधीधाम टाउनशिप क्षेत्रों के लिए पट्टा किराया निर्धारण से संबंधित नीति प्राप्त हो जाने के पश्चात् इस प्राधिकरण को इस मामले में अंतिम विचारार्थ समय लगेगा। चूंकि गांधीधाम टाउनशिप भूमि की दर संरचना की वैधता 30 सितंबर, 2016 को समाप्त हो गई है, यह प्राधिकरण गांधीधाम टाउनशिप भूमि की वर्तमान दर संरचना को उसकी समाप्ति की तारीख से 31 मार्च, 2017 तक अथवा केपीटी द्वारा दायर प्रशुल्क प्रस्ताव के आधार पर संशोधित पट्टा किरायों की अधिसूचना की तारीख तक जो भी पहले हो, केपीटी द्वारा यथा प्रस्तावित, विस्तार करता है।

6.1 सरकार द्वारा जारी भूमि नीति दिशानिर्देश 2010 (जिसके आधार पर गांधीधाम टाउनशिप भूमि की दर संरचना अप्रैल, 2012 में नियत की गई थी) अनुबद्ध करते हैं कि इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित पट्टा किरायों में 2 प्रतिशत वार्षिक की वृद्धि तब तक होती रहेगी जब तक उनका संशोधन इस प्राधिकरण द्वारा नहीं किया जाता। इस प्राधिकरण द्वारा अप्रैल, 2012 में अनुमोदित आदेश में भी इस संबंध में विशिष्ट शर्त निर्धारित की गयी थी। यह शर्त पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी संशोधन भूमि नीति दिशानिर्देश, 2014 में भी अभिभावी है। चूंकि मौजूदा पट्टा किराया अनुसूची में जब तक पट्टा किरायों में इस प्राधिकरण द्वारा संशोधित नहीं किया जाता तब तक पट्टा किरायों में 2 प्रतिशत की दर पर वार्षिक वृद्धि सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप है। इस लिए 2 प्रतिशत की दर पर वार्षिक वृद्धि गांधीधाम टाउनशिप भूमि की दर संरचना की विस्तारित अवधि के दौरान लागू रहेगी।

6.2 फिर भी, इस संबंध में यह नोट किया जाता है कि 2 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ मौजूदा पट्टा किरायों का विस्तार वर्तमान परिदृश्य में निर्वात से बचने के लिए अंतरिम व्यवस्था है। इस संबंध में केपीटी द्वारा दायर प्रस्ताव के आधार पर गांधीधाम टाउनशिप के लिए निर्धारित पट्टा किराया को पूर्वव्यापी प्रभाव दिया जाना होगा, जैसा कि केपीटी ने अनुरोध किया है।

7. परिणाम में और सामूहिक विचार-विमर्श के उपरांत ऊपर बताये गए कारणों से यह प्राधिकरण, गांधीधाम टाउनशिप भूमि की मौजूदा दर संरचना की वैधता को उसकी समाप्ति की तारीख से 31 मार्च, 2017 तक अथवा केपीटी द्वारा प्रशुल्क प्रस्ताव के आधार पर संशोधित पट्टा किरायों की अधिसूचना के प्रभावी होने की तारीख तक, जो भी पहले हो, विस्तार करता है।

टी. एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन-III/4/असा./454/16]

**TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS
NOTIFICATION**

Mumbai, the 15th February 2017

No. TAMP/20/2010-KPT.—In exercise of the powers conferred by Section 49 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the existing rate structure for Gandhidham Township land of KPT as in the Order appended hereto.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

Case No.TAMP/20/2010-KPT

Kandla Port Trust

Applicant

QUORUM:

- (i) Shri T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
- (ii) Shri Rajat Sachar, Member (Economic)

ORDER

(Passed on this 8th day of February, 2017)

This case relates to a proposal filed by Kandla Port Trust (KPT) for extension of the validity of the rate structure for Gandhidham Township Land of KPT.

2. The lease rental for the Gandhidham Township Land of KPT was last revised by this Authority vide Order dated 9 April, 2012. The lease rental revised by this Authority was given retrospective effect from 1 January, 2009 and validity was prescribed for a period of five years, i.e. up to 31 December, 2013. Thereafter, this Authority has extended the validity of the existing rate structure for Gandhidham Township Land of KPT from time to time at the request of KPT.

3. The validity of the existing rate structure for Gandhidham Township Land of KPT was last extended based on the request of KPT vide Order No.TAMP/20/2010-KPT dated 6 May, 2016 from the date of expiry till 30 September, 2016 or till the date of effect of notification of the revised rentals based on the tariff proposal to be filed by the KPT, whichever is earlier.

4. It is relevant here to state that, the KPT, vide its email dated 11 April, 2016 has submitted its proposal for revision of rate structure for Gandhidham Township Land. The proposal was taken on consultation with the stakeholders. A joint hearing on the case in reference was held on 30 July, 2016. The KPT has vide its letter dated 2 December, 2016 submitted additional information/ clarifications sought by us vide our letter dated 2 August, 2016.

5.1. Para 5.7 of Amended Land Policy Guidelines (LPG) 2014 states that the Policy is applicable for all Major Ports except for land relating to the Township areas of KPT, Mumbai Port Trust (MBPT) and Kolkata Port Trust (KOPT) for which separate policy will be formulated. Hence, vide our letter No.TAMP/8/2014-Genl., dated 10 April, 2014 and 9 February 2016 the MOS was requested to clarify under which LPG the revision of Township area of Kandla will be governed till separate policy is formulated. This was followed up by letters No.TAMP/25/2016-KPT dated 22 April, 2016, 28 June, 2016 and 14 July, 2016.

5.2. In the context, the MOS vide its letter no. 8/(19)/2016-TAMP, dated 02 August, 2016 has informed that a proposal seeking approval of the Union Cabinet on Land relating to Gandhidham Township is being prepared by the MOS. The MOS has, therefore, requested to keep on hold the proposal of KPT for revision of rate structure of Gandhidham Township of KPT and take up after the MOS conveys the policy in this regard. The policy from MOS in this regard is awaited.

5.3. In the meantime, the KPT has, vide its letter dated 18 November 2016 requested the Authority to allow it to continue to charge at the existing rates for a further period of 6 months i.e. up to 31 March, 2017, subject to condition that revised rates will be made applicable with retrospective effect.

5.4. In view of the position brought out in para 4.2. above, it will take time for the case for final consideration of the Authority even after receipt of the policy relating to the fixation of lease rent for Gandhidham township areas from the MOS. Since the validity of the rate structure for Gandhidham Township Land has expired on 30 September, 2016, this Authority extends the validity of the existing rate structure of the Gandhidham township land from the date of its expiry till 31 March, 2017 or till the date of effect of notification of the revised lease rentals based on the tariff proposal filed by the KPT, whichever is earlier as sought by KPT.

6.1. The Land Policy Guidelines of 2010 issued by the Government (based on which the rate structure for Gandhidham Township Land has been fixed in April 2012) stipulates that the lease rentals approved by this Authority shall be escalated by 2% per annum till they are revised by this Authority. The Order approved by this Authority in April 2012 also prescribes a specific condition in this regard. This condition also prevails in the revised Land Policy Guidelines, 2014 issued by the Ministry of Shipping. Since, the existing Schedule of lease rent already prescribes annual escalation @ 2% in the lease rentals till such time the rates are revised by this Authority and in line with the guidelines issued by the Government, the annual escalation @ 2% will continue to apply during the extended validity period of the rate structure for Gandhidham Township Land.

6.2. However, it is to be noted in this regard that the extension of the existing lease rentals with an annual escalation of 2% is only a provisional arrangement to avoid a vacuum in the current scenario. The lease rentals to be fixed for the Gandhidham Township based on a proposal filed by the KPT in this regard will have to be given retrospective effect, as requested by the KPT.

7. In the result, and for the reasons given above and based on the collective application of mind this Authority extends the validity of the existing rate structure for Gandhidham Township Land from the date of its expiry till 31 March, 2017 or till the date of effect of notification of the revised lease rentals based on the tariff proposal filed by the KPT, whichever is earlier.

T. S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.-III/4/Exty./454/16]